



भूमि संसाधन विभाग
Department of Land Resources
Ministry of Rural Development
Government of India



मध्यप्रदेश शासन



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ

विशेषताएं

- डिजिटल भूमि रिकॉर्ड
- हवाई सर्वेक्षण और नई तकनीक
- वेब जीआईएस प्लेटफॉर्म
- भू-स्थानिक डेटा
- ट्रांसपेरेंट सिस्टम

लाभ

- मालिकाना हक की स्पष्टता
- शहरी विकास में तेजी
- क्रेडिट और लोन की आसानी
- संपत्ति कर वसूली में सुधार
- आपदा प्रबंधन में सहायक

अध्यक्षता

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मुख्य अतिथि

शिवराज सिंह चौहान

केन्द्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण
तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय

विशिष्ट अतिथि

डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी

केन्द्रीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास तथा संचार मंत्रालय

18 फरवरी, 2025 | पूर्वाह्न - 11:00 बजे | रायसेन, मध्यप्रदेश



सीधा प्रसारण

Webcast.gov.in/mp/cmevents



@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhyapradesh



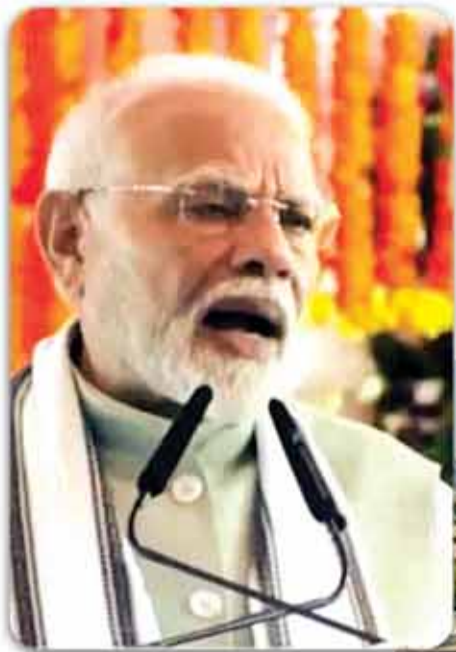
@Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP



jansamparkMP

खुशहाल मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने और उसके संचालन के लिए बुनियादी ढांचा बेहद मजबूत और सुगम



मध्य प्रदेश में विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनियां, बिजनेस लीडर्स, उद्योगपति, निवेशक और विशेषज्ञ, यह सभी एक मंच पर साथ आ रहे हैं। यह मंच है वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी जीआईएस)। राज्य में निवेश के अनंत अवसरों को प्रदर्शित करने वाला यह महासम्मेलन 24 एवं 25 फरवरी 2025 को राज्य की राजधानी भोपाल में आयोजित हो रहा है। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए दृढ़संकल्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के विकास को नई उंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेश की अनंत संभावनाओं के साथ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा और जनसंख्या के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है।

मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य व्यापार संचालन और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। यह कार्यक्रम नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए आने वाली बाधाओं को कम करता है। प्रमुख सुधारों में ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंसिंग और परमिट अनुमोदन जैसी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण शामिल है। इससे उद्यमियों के लिए समय और लागत में काफी कमी आई है। राज्य ने निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए समर्थन और पारदर्शी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हुए, क्लोयर्स और अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने के लिए इन्वेस्ट एमपी सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है।



वो सबकुछ मौजूद है जो उद्योगों के लिए जरूरी है

- मध्य प्रदेश में 3 लाख किलोमीटर से अधिक फैला हुआ विस्तृत सड़क नेटवर्क है। यहां 5 वाणिज्यिक हवाई अड्डे और 26 हवाई पट्टियों की व्यवस्था है।
- प्रदेश में 1.25 लाख एकड़ से अधिक औद्योगिक भूमि उपलब्ध है। इसके साथ 112 विकसित या विकासशील औद्योगिक क्षेत्र और 14 ग्रीनफील्ड साइट्स मौजूद हैं।
- राज्य जल-आपूर्ति के क्षेत्र में भी अग्रणी है। यहां 1,000 एमएसीएम से अधिक प्रचुर औद्योगिक जल आपूर्ति की उपलब्धता है।
- प्रदेश में प्रतिस्पर्धी टैरिफ के साथ 24x7 स्थिर बिजली आपूर्ति की जाती है। बुनियादी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार विशेष सुविधा भी देती है।
- मध्य प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के पास आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, ग्लोबल रिकल पार्क, आईटीआई और मेगा आईटीआई की उपस्थिति है।
- राज्य खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, सब्जियों और फलों का अग्रणी उत्पादक है।

लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग

राज्य में 40 एमएटी की पंढारण क्षमता और 13.2 एमएटी की कोल्ड स्टोरेज क्षमता उपलब्ध है। मध्य प्रदेश स्टील साइडो के निर्माण में अग्रणी राज्य है। इंदौर और भोपाल में आगामी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इस क्षेत्र में विकास को नया आवाम देगा।

वस्त्र और परिधान

भारत के जैविक कपास उत्पादन में 43% और विश्व के जैविक कपास उत्पादन में 24% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा बड़ी कपड़ा मिलें और हजारों करघे संचालित हैं। इंदौर में रेडीमेड गारमेंट और अपरेल क्लस्टर में 1,200 से अधिक इकाइयाँ हैं। मध्य प्रदेश चंदेरी, टसर महेश्वरी, चाप प्रिंट, हैड-ब्लॉक प्रिंट, बाटिक प्रिंट आदि जैसे पारंपरिक वस्त्रों का घर है।



ऑटोमोबाइल उद्योग में मजबूत

मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, पीथमपुर और देवास भारत के प्रमुख ऑटो क्लस्टर हैं। प्रदेश में 2800 से अधिक इंजीनियरिंग निर्माता और 10 से ज्यादा मूल उपकरण निर्माता हैं। प्रदेश का नेटरेक्स एशिया का सबसे लंबा हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक, जिसकी लंबाई 11.3 किमी है। यहां 14 टेस्ट ट्रैक और 5 ऑटो विशिष्ट प्रयोगशालाएँ हैं। 4,500 हेक्टेयर पीथमपुर ऑटो क्लस्टर में 25,000 से ज्यादा लोग कार्यरत हैं।

कृषि, खाद्य एवं दुग्ध प्रसंस्करण में अग्रणी

प्रदेश दलहन और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। खाद्यान्न और फूलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य जैविक फसल उत्पादन में अग्रणी है। यहां 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 70 से ज्यादा बड़ी और 3800 से भी अधिक एमएसएमई इकाइयाँ कार्यरत हैं।

फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण एवं स्वास्थ्य सेवा

राज्य में 270 से अधिक फार्मा इकाइयाँ मौजूद हैं। फार्मा सेक्टर में 1,00,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं। बड़ी संख्या में ड्रग्स/एचओ-जीएमपी, यूएसएफडीए अनुपालन इकाइयाँ मौजूद हैं। राज्य ने वित्त वर्ष 2022 में 10,770 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात किया। प्रदेश से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, रूस, नीदरलैंड, जर्मनी और ब्राजील सहित 150 से ज्यादा देशों को निर्यात होता है। 20 से अधिक मेडिकल डिवाइस इकाइयाँ और 250 से ज्यादा इकाइयाँ मेडिकल डिवाइस के पुर्जे बनाती हैं। उच्चैक की विक्रम उद्योगपुरी में 360 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क फैला हुआ है।



सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन

मध्य प्रदेश में 4 आईटी एनआईजेड, 10 आईटी पार्क, 2 इंफ्लो क्लस्टर और 150 से ज्यादा इंफ्लो क्लस्टर मौजूद हैं। प्रदेश में 2500 से अधिक डीपीआईआईटी पंजीकृत स्टार्टअप हैं, जिसमें से 280 से अधिक आईटी-सेवा आधारित स्टार्टअप हैं। राज्य में आईआईटी, आईआईएम और 330 से भी ज्यादा तकनीकी संस्थान और आईटीआई की उपस्थिति के साथ उच्चतक कुशल प्रतिभा पूरा की उपलब्धता है। मध्य प्रदेश भारत का टाइगर राज्य है। यहां 11 राष्ट्रीय उद्यान और 6 बाघ अभयारण्य स्थित 24 वन्यजीव अभयारण्य हैं। 3 खुलेसकी विश्व धरोहर स्थल (सांची, खजुराहो और मंमखेटक) और उज्जैन, ओकरेश्वर, अमरकंटक जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण विरासत स्थल हैं।

रोजगार और उद्योग का हब बन रहा मध्य प्रदेश

पीएम मोदी की नीतियों को अपनाने में अग्रणी है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार

केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को मप्र की मोहन सरकार ने बड़ी कुशलता के साथ अपनाया है। उन पर अमल करके राज्य को खुशहाल बनाया जा रहा है। अब रोजगार और उद्योग का बड़ा हब बन रहा है। डॉ. मोहन यादव सरकार के डबल इंजन से खुशहाली और उन्नति के पथ पर मप्र लगातार दौड़ रहा है, लेकिन अब तीसरा नई ऊर्जा वाला इंजन (बजट) प्रदेश को मिला है, इससे विकास की गति तीन गुना हो जाएगी।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से लेकर किसान और युवाओं तक जो अभूतपूर्व सीमांतें दी हैं, उसका मध्य प्रदेश में भी खासा प्रभाव दिखाई देगा। विशेष रूप से 24 एवं 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 को लेकर निवेश की संभावनाओं को काफी मजबूती मिली है। बजट में जो घोषणाएँ हैं, उससे न केवल उद्योग जगत सशक्त होगा, बल्कि



आर्थिक प्रगति ही प्राथमिकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता में रखा है, उसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सतत आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट में उद्योग जगत सहित युवाओं और किसानों को सीमांतें मिली हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 की संभावनाओं को आम बजट ने और अधिक विस्तार दिया है। मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों और बेहतरीन वातावरण को इस बजट में जो ऊर्जा दी है, वह आने वाले समिट में स्पष्ट दिखाई देगा।

किसानों को राहत- केसीसी से 5 लाख का कर्ज

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों की प्राथमिकता में कृषि क्षेत्र भी है। केंद्रीय बजट में अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस किया गया है। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। इन सीमांतों का सीधा लाभ मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कृषि और कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश करने वालों को मिलेगा। आम बजट में उद्योगों के लिए जो घोषणाएँ की गई हैं, वह मध्य प्रदेश में मौजूदा कंपनियों के साथ आने वाले निवेशकों के लिए भी सीमांतें हैं। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।

लघु खनिजों समेत खनन सेक्टर को फायदा

बजट में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि निवेश हमारी सरकार का तीसरा इंजन है। ग्रीन एनर्जी और ईवी तकनीक को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। अब देश में राज्य खनन सूचकांक की स्थापना होगी। इससे लघु खनिजों समेत खनन सेक्टर को फायदा होगा। खनन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद है। खनन को लेकर निवेशकों का एक सम्मेलन भोपाल में पहले आयोजित किया जा चुका है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए थे।

अक्षय ऊर्जा में मप्र में हो रहे नवाचार

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष प्रकार की आरई नीति वाला पहला राज्य है। प्रदेश के सांची को नेट जीरो कार्बन अवधारणा पर मध्य प्रदेश के पहले सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। नमोदापुरम में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए समर्पित विनिर्माण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। लगभग 62 गौगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता और 11 गौगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता के साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधन प्रदेश में उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश में 2,750 मेगावाट (2.75 गौगावाट) की कुल क्षमता वाले 5 बड़े सौर संयंत्र हैं।

भगवान बुद्ध से जुड़े स्थान हो रहे विकसित
देश के शीर्ष 50 टूरिज्म स्पॉट को राज्यों की सहायता से और विकसित किया जाएगा। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थान विकसित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में सांची बौद्ध अनुयायियों के लिए धार्मिक पर्यटन का विशिष्ट स्थल है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम का लाभ बजट में जो गई उस घोषणा से मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि मेडिकल टूरिज्म के लिए वीजा नियमों को आसान किया जाएगा।

20 हजार करोड़ किए गए आवंटित

मध्य प्रदेश का इंदौर स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है। इनोवेटिक्स के लिए बजट में 20 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नेस्ट जनरेशन के स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड पर विचार किया जाना मध्य प्रदेश के युवाओं को नए अवसर दे रहा है। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया गया है। गारंटी फंड में भी कमी होगी। एक्सिलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ रुपये का पेंशन स्थापित योग्य है।

